Vol 7 Issue 4 May 2017

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 IMPACT FACTOR : 5.1651(UIF) VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | MAY - 2017

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

लोकतंत्र एवं संचार माध्यम : चुनौतियाँ एवं समाधान

सोहन लाल
सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

शोध सार

भारतीय लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम की भूमिका सशक्त है, इसके बिना लोकतांत्रिक भव्य भवन की कल्पना ही नही की जा सकती। लोकतंत्र का मकसद भी यही होता है कि तमाम सामंती चिह्न, भाषा, व्यवहार तिरोहित हो और लोकतांत्रिक सहभागी संस्कृति विकसित हो। समाज के वंचित तबकों के उत्थान में विकासपरक कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया को सामाजिक क्रांति के अभिकर्त्ता की भूमिका निर्वहन करना था, यद्यपि मीडिया के द्वारा जनता के हितप्रहरी के भूमिका का समय–समय पर निर्वहन किया है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया जो काम कर रहा है वह अन्य क्षेत्रों से बेहतर है लेकिन इससे संतोष नही किया जा सकता। भारतीय संदर्भ में जो भूमिका मीडिया ने स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता पश्चात् निभाई है उस पर खबरपालिका को गर्व है लेकिन हाल ही के वर्षो में संचार माध्यमों का रूझान परिवर्तित हुआ है। इसलिए आज मीडिया आलोचना का विषय बना हुआ है। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, संतुलित मीडिया भ्रष्टाचार रोकने, अनुवीक्षण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मीडिया लोकतंत्र की समस्त चुनौतियों का सामना कर एक सफल लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है।

समस्या समाधान के उपाय प्रसांगिक एवं उपयोगी होते हुए भी इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग एवं आमजन में व्यापक आम सहमति के साथ सतत् जागरूकता परम आवश्यक है, लेकिन इस विषय में राजनीतिक अभिजन वर्ग एवं स्वयं मीडिया में गंभीर दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता का निरन्तर अभाव दृष्टिगोचर हुआ है।

शब्द संकेत

लोकतंत्र, संचार माध्यम, सहभागी संस्कृति, सामाजिक क्रांति, राजनैतिक चेतना, चुनौतिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया।

शोध–आलेख

लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण एवं अध्ययन करने से पहले हमें लोकतंत्र एवं मीडिया की प्रकृति पर दृष्टिपात करना अति आवश्यक है चूंकि आज के दौर में संचार माध्यमों, तमाम सवाल खड़े हो रहें हैं। अंग्रेज दार्शनिक एडमण्ड वर्क ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तम्भ खबरपालिका अर्थात् मीडिया हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका तलाशने के लिए हमें लोकतंत्र में इन स्थितियों को समझने के लिए लोकतंत्र और संचार माध्यम को अलग–अलग देखते हुए दोनों में समन्वय खोजना हैं।

लोकतंत्र से आशय

लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी यूनानी भाषा से निकला है। यह दो ग्रीक शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है जिसका आशय है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन के अनुसार– ''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।'' सीले के शब्दों में –''लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है।'' इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों ने आजादी से लेकर आज तक सुहाना सफर तय किया है। दरअसल लोकतंत्र राजनीतिक परिस्थिति ही नही है या सामाजिक परिस्थिति मात्र नही है बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी नैतिक एवं आध्यात्मिक धारणा भी है। यह शासन संचालक की पद्धति मात्र नही है, जीवनयापन की एक गतिशील पद्धति भी है। लोकतंत्र में चाहे कितनी भी त्रुटियाँ क्यों ना हो किन्तु शासन का यह सर्वोत्तम साधन आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि उसमें विकास की क्षमता है। लोकतंत्र की समान्यतः तीन विशेषताएँ कही जा सकती है–

- जनता का प्रतिनिधित्व।
- जनता के हितो का रक्षण।
- जनता के प्रति उत्तरदायित्व।

बीते 69 वर्षों में हमनें लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। लोकतंत्र की बुनियादी मान्यता है समाज में शान्तिपूर्ण एवं वैधानिक उपायों से बदलाव लाया जा सकता है। सहभागिता लोकतंत्र की बुनियाद है।

संचार माध्यम से आशय

संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिन्दी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है जिसका आशय है सामान्य भागीदारी युक्त सूचना। चूंकि संचार समाज में घटित होता है। सामाजिक सम्बन्धों को दिशा देने अथवा निरन्तर प्रवाहमान बनाए रखने की प्रक्रिया ही संचार है। डॉ. मरी के मत सें– ''संचार सामाजिक उपकरण का सामंजस्य है।'' राजनीति शास्त्र के विचारक लुसियन पाई के मत में –''सामाजिक प्रक्रियों का विशलेषण ही संचार है।'' मीडिया शब्द से आशय है दो बिन्दुओं (सम्प्रेषक और श्रोता) का मिलान होता है। इससे स्पष्ट होता है कि मीडिया सामाजिक सम्बन्धों को विकासपरक स्वरूप प्रदान करता है। मीडिया समाज के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक के विकास से जुड़ा है।

1956 में संचारविद् फ्रेड साइवर्ट, थियोडोर पीटरसन, बिल्बर श्रेय ने वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मीडिया के सिद्धांतों का विस्तार से जिक्र किया हैं। इन सिद्धांतों के प्रकाशित होने के बाद 1983 में डेनिस मेक्विल ने दो अन्य सिद्धांत विश्व पटल के समक्ष रखे। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन की खास वजह बदलती परिस्थितियाँ रही है। मीडिया के सिद्धांत निम्नानुसार है–

1. उदारवादी मीडिया सिद्धांत (व्यक्तिगत, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था)
2. सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ–साथ सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित व्यवस्था)
3. विकास संचार सिद्धांत (विकासपरक सिद्धांत पर आधारित संचार व्यवस्था)
4. लोकतांत्रिक सहभागिता सिद्धांत (लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित व्यवस्था)

लोकतंत्र और मीडिया

भारतीय लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यम की भूमिका सशक्त है, इसके बिना लोकतांत्रिक भव्य भवन की कल्पना ही नही की जा सकती। लोकतंत्र का मकसद भी यही होता है कि तमाम सामंती चिह्न भाषा, व्यवहार तिरोहित हो और लोकतांत्रिक सहभागी संस्कृति विकसित हो। समाज के वंचित तबकों के उत्थान में विकासपरक कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया को सामाजिक क्रांति के अभिकर्ता की भूमिका निर्वहन करना था। यद्यपि मीडिया के द्वारा जनता के हितप्रहरी के भूमिका का समय–समय पर निर्वहन किया है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया जो काम कर रहा है वह अन्य क्षेत्रों से बेहतर है लेकिन इससे संतोष नही किया जा सकता। भारतीय संदर्भ में जो भूमिका मीडिया ने स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता पश्चात् निभाई है उस पर खबरपालिका को गर्व है लेकिन हाल ही के वर्षो में संचार माध्यमों का रूझान परिवर्तित हुआ है। इसलिए आज मीडिया आलोचना का विषय बना हुआ है। एक सशक्त प्रजातंत्र तभी अपने अधिकत क्षमता का दोहन कर सकता है। जब आमजन शासन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाए, ऐसा भी कहा जाता है कि लोक मत ही ईश्वर का मत हैं।

आवाज़े खलक, अवाज़े खुदा।

लोकमत के निर्माण मे मीडिया प्रभावकारी भूमिका का निर्वहन करता हैं। ऐसे तभी हो सकता है जब उसकी राजनीतिक चेतना का स्तर उच्च हो। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, संतुलित मीडिया भ्रष्टाचार रोकने, अनुवीक्षण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मीडिया लोकतंत्र की समस्त चुनौतियों का सामना कर एक सफल लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करता है। मीडिया प्रशासन और जनता के मध्य महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम कर रहा है।

संचारविद् मैक्स मैककाम्ब ने तीन प्रकार के मीडिया का एजेण्डा सैटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।

- पब्लिक एजेण्डा।
- मीडिया एजेण्डा।
- पॉलिसी एजेण्डा।

आमजन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ा हुआ पब्लिक एजेण्डा मीडिया एजेण्डे की जरिये वह राजसत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसे पॉलिसी एजेण्डे का अंग बनाया जा सके। मीडिया एजेण्डा लोगो के मुद्दों को राजसत्ता तक पहुंचाता है। राजसत्ता का ध्यान पब्लिक एजेण्डे की ओर आकर्षित करता है, जबकि पॉलिसी एजेण्डा राजसत्ता द्वारा पब्लिक एजेण्डे को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। वह इन तीन एजेण्डों के तालमेल को आवश्यक मानते हैं लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसा नही पाया जाता। व्यवहार में मीडिया और राज्य एजेण्डा साथ–साथ चलते है। इसमें पब्लिक एजेण्डा हाशिये पर चला जाता है। कुछ अवसरों पर पब्लिक के लामबंद होने पर मीडिया अपना एजेण्डा बदलकर पब्लिक एजेण्डे के साथ हो जाता है। इन सभी दोषों के बाबजूद भी यह परिस्थिति अधिनायकवाद से काफी बेहतर है। इसमें सुधार की गुंजाइश है। अधिनायकवादी व साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले देशों में मीडिया के लिए राज्य एजेण्डा पहला और अंतिम विकल्प होता है। किसी भी परिस्थिति में राज्य के एजेण्डे को चुनौति नही दी जा सकती। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में मीडिया लोकतांत्रिक सहभागिता एवं सामाजिक सरोकारों के लक्ष्य के साथ विकासपरक दृष्टिकोण रखता है।

मीडिया के स्वतंत्र विकास के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां

ब्रिटेन की 'द इक्नोमिस्ट' मैग्जीन ने 2007 में विश्व के 167 देशों में सर्वे किया जिसमे बताया गया कि आज कई देशों में अधिनायकवाद फल–फूल रहा है, जो मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है। इन देशों में मीडिया कठपूतली मात्र रहा है, जो राज्य सरकारों के इशारों पर नृत्य करता है जो सत्ता के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है उसे दमनात्मक तरीके से कुचलने में कोताही बर्दाश्त नही की जाती। मीडिया के पास राजसत्ता के साथ मिलकर चलना उसके समक्ष अंतिम विकल्प है। मीडिया संदेशों के सेंशरशिप और प्री सेंशरशिप का प्रावधान है। यही कारण है कि इन देशों में सैंकड़ो पत्रकारों को जान से हाथ धोना पड़ता है और अनेकों को यातनाओं का शिकार बनना पड़ता है।

लेनिन ने जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंचार व्यवस्था को सर्वाधिक उपयुक्त अस्त्र माना। साम्यवादी देशों में मीडिया हमेशा भय के साये में कार्य करता है। सत्ता के विपरित जाने पर मीडिया के लिए दण्डात्मक प्रावधान किए गए है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परामर्शदात्री संस्था ने मीडिया की आजादी पर आधारित अपनी रिपोर्ट 'विदाउट बॉर्डर' में उल्लेख किया है– 2013 में विश्व में 71 मीडियाकर्मी मारे गए, 826 को जेलबन्द किया गया,

2160 को धमकाया गया, 87 का अपहरण किया गया, 77 को जान बचाने के लिए अन्य देशों को अपनी शरणस्थली बनाना पड़ा। इनमें से अधिकतर घटनाएं अधिनायकवादी देशों में घटित हुई। यही कारण है कि इनका विरोध वैश्विक स्तर पर होता रहा है।

सोलहवीं शताब्दी में उदारवादी बुद्धिजीवियों (जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, जेफर्सन) ने अधिनायकवादी व्यवस्था को नागरिक स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक खतरा बताया। इन उदारवादियों ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की बात कही जिसमें मीडिया बिना किसी दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कह सके। किसी भी राज व्यवस्था के विकास के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं की अपनी महत्ता है। यही स्वतंत्रता मीडिया को भी मिलनी चाहिए तभी एक स्वतंत्र तंत्र का विकास हो पाएगा, जो अधिकतम् लोगों के अधिकतम हितों की साधना कर पाएगा। नवीन परिदृश्य ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के संकेत दिए कि कैसे मीडिया समाज के सभी तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों ने मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया। प्रायोजित मीडिया के जरिये अपने व्यापारिक व राजनीतिक हितों की पूर्ति करने लगा। मीडिया को उद्योग का स्वरूप दिया गया। मीडिया जनमत की बजाए पूंजीपतियों व राजनीतिज्ञों का हथियार बनकर बेलगाम हो गया। पूंजीवादी देशों में मीडिया की प्रकृति केन्द्रीयकरण की हो गई।

पिछली शताब्दी के प्रारम्भ मे इस बात पर जोर दिया गया कि मीडिया के लिए वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सामाजिक सरोकार। 1947 में गठित रॉयल कमीशन ने कहा कि प्रेस काउंसिल होनी चाहिए जो मीडिया पर एक निगरानी तंत्र की भूमिका का निर्वहन कर उन्हे उनके उत्तरदायित्वों का एहसास करा सके। इस वर्ष हचिंस कमीशन ने आचार संहिता को ध्यान में रखकर समाज तक संदेश प्रसारित करने का जिम्मा मीडिया को सौंपे जाने की बात कही। दुनियाँ के अधिकतर देशों के द्वारा अपनी–अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप इन आयोगों की सिफारिशों के मध्यनजर प्रावधान जारी किए गए। उपनिवेशिक दासता से स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्था कुपोषण एवं गुलाम मानसिकता की शिकार थी जिनमें मीडिया को विकासपरक संचार का कार्य करना था। लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करने के अहम दायित्व के निर्वहन में अनेकानेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेक्विल ने लोकतांत्रिक सहभागिता सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि मीडिया का लोकतांत्रिकरण एवं विकेन्द्रीयकरण अति आवश्यक है।

लोकतांत्रिक समाज में मीडिया को सशक्त एवं कारगर बनाने के सुझाव

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में मीडिया के द्वारा आमजन की परिस्थितियों के मध्यनजर विकासपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया लेकिन फिर भी इसमें कई सारी खामियां है। आई.आर.एस. के 2007 के आंकड़े बताते है कि इलेक्ट्रनिक मीडिया केवल अपनी टी.आर.पी. देखता है। आजादी के 69 वर्ष बाद भी मीडिया जन सामान्य तक नही पहुंच पाया। इसके कारण चाहे कुछ भी क्यों ना रहे हों, इसे शुभ संकेत नही माना जा सकता। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया सशक्त एवं कारगर हो, इसके लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं–

- लोकतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार तो देता है लेकिन इस व्यवस्था में अधिकार के साथ–साथ कर्त्तव्य पालन भी अनिवार्य होता है। लोकतंत्र अधिकार और कर्त्तव्य में असंतुलन की इजाजत नही देता। फिर मीडिया पर तो लोकतंत्र की सशक्त पहरेदारी का जिम्मा है, उसे इस गंभीर दायित्व से मुँह नही मोड़ना होगा।
- मीडिया को मार्शल मैक्लूहान की बात ''मीडिया इज मैसेज'' हमेशा याद रखनी होगी क्योंकि इससे लोकतंत्र में सार्थक सूचना एवं संचार क्रांति आ सकती है।
- मीडिया को खुद जज बनने की प्रवृत्ति से बचना होगा क्योंकि लोकतंत्र में न्याय के लिए न्यायपालिका का प्रावधान है, न कि खबरपालिका का। आरूषि हत्याकाण्ड से सबक लेने की जरूरत है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था, शिक्षा, तकनीकी विकास और सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के लिए मीडिया को आगे आना होगा।
- दलित, महिला, ग्रामीण विकास से मुँह फेरने की प्रवृत्ति से बचना होगा।
- राष्ट्र की एकता, अखण्डता तथा मानवाधिकार के मुद्दो को अहम् स्थान देना होगा।
- भारतीय जीवन मूल्यों एवं लोक संस्कृति को प्रवाहमान बनाए रखने की भूमिका का निर्वहन करना होगा।
- पर्यावरण संरक्षण चेतना जागृत करने के प्रयास करने होंगे।
- स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को उत्साह के साथ जनमानस के मानसिक पटल पर अंकित करने के प्रयास करने होंगे।
- बहुसंख्यक समाज के साथ–साथ अल्पसंख्यक समाज के सरोकारों को तवज्जों देनी होगी।
- विकासपरक दृष्टिकोण को तवज्जों देनी होगी।
- लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए आमजन को प्रेरित करना होगा तभी लोकतांत्रिक मूल्य जीवन्त हो पाऐंगे।
- सकारात्मक वातावरण का सृजन करना होगा।
- सहभागी लोकतंत्र विकसित करने का पर्यावरण सृजित करना होगा।
- भारतीय प्रेस परिषद का प्रभावी पुनर्गठन हो ताकि मुद्रण मीडिया के लिए आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू हो।
- मुद्रण मीडिया की भांति इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए आचार संहिता का प्रावधान हो।
- मीडिया आयोग का गठन हो।
- मीडिया स्वनियमन तंत्र विकसित करे।
- मीडिया आमजन व सरकार के बीच सेतुबंध का कार्य करे।
- मीडिया सभी संभव चीजों को प्रकाश मे लाये।
- मीडिया न केवल जनसामान्य में अधिकारों को पोषित पल्लवित करे अपितु उनमें दायित्व निर्वहन की भावना भी संचारित करे।

सुधार एक सतत् चलायमान प्रक्रिया है। इसलिए सुधारों की सूची अनन्तिम होती है जिसमें गत अनुभव एवं नये सुझाव जुड़ते चले जाते है।

उपसंहार

एक सफल लोकतंत्र में मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। मीडिया को समाज की आवाज कहा जाता है। हमारे देश में संकट का दौर जब भी कभी आया, प्रिंटिंग और इलेक्ट्रोनिक मीडिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में मीडिया की भूमिका निखरकर सामने आती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में मीडिया समाज के एक वर्ग विशेष और क्षेत्र विशेष की आवाज बनकर रह गया है।

इसके परिणामस्वरूप मीडिया समाज और देश की परिस्थितियों को समझने से दूर होता दिखाई दे रहा है। मीडिया की आलोचना उसे अपनी कार्यप्रणाली में कुछ जरूरी सुधार करने के लिए मजबूर करती है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लोकतंत्र में आमजन के सशक्तिकरण के लिए जनसंचार माध्यमों में व्याप्त व्याधियों एवं न्यूनताओं के निराकरण की ओर समग्र चिंतन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। समस्या समाधान के उपाय प्रसांगिक एवं उपयोगी होते हुए भी इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग एवं आमजन में व्यापक आम सहमति के साथ सतत् जागरूकता परम आवश्यक है।

सारांश में कहा जा सकता है कि सवाल गंभीर जरूर हैं, लेकिन ऐसे सवालों के उत्तर खोजे जाऐंगे, ऐसा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मीडिया की भूमिका के साथ–साथ लोकतंत्र के सम्पूर्ण तत्वों को अपनी भूमिका पर सोचना होगा। समस्या समाधान एक निरन्तर चलायमान प्रक्रिया है। इसमें सुधारों की सूची अनन्तिम होती है, जिसमे गत अनुभव एवं नये सुझाव जुड़ते चले जाते हैं। सहभागी विकासपरक लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए मीडिया में समय–समय पर उत्पन्न विभिन्न कठिनाईयों, कमियों एवं बुराईयों पर नियन्त्रण पाने के लिए यथासंभव प्रयास हुए है, लेकिन इस विषय में राजनीतिक अभिजन वर्ग एवं स्वयं मीडिया में गंभीर दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता का निरन्तर अभाव दृष्टिगोचर हुआ है।

संदर्भ सूची

1.डॉ. फड़िया, बी. एल. एवं डॉ. जैन, पुखराज – भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृष्ठ 506।
2.तिवारी, ममता (2008) – चुनाव, लोकतंत्र, मीडिया, डायमण्ड पब्लिशर्स
3.डेनिस, मेक्विल(1983)– सप्लीमेंटरी थ्योरी ऑफ प्रेस
4.प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (2013) रिर्पोट्स 'विदआउट बॉर्डर'
5.रॉयल कमीशन ऑन द प्रेस रिर्पोट (1947)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org